Volume-08
Issue-05
May-2021

ISSN: 2349-7637 (Online)
RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal
https://rhimrj.co.in/ [Peer-Reviewed Journal]

भारत में वैश्वीकरण

डॉ. नीलम कान्त

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उ.प्र.

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 May 2021

Keywords
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यिक उधार (ई.सी. बी.), नेटस्केप आई.पी.ओ.।

***Corresponding Author**
Email: *kantneelam@gmail.com*

ABSTRACT

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव और गैर–मानवीय गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय और पारसांस्कृतिक एकीकरण के कारण, पाठ्यक्रम और परिणाम शामिल हैं। भारत को मुगल युग के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त था, क्योंकि इसका विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 32.9 प्रतिशत हिस्सा और विश्व जनसंख्या का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा था। भारत में उत्पादित वस्तुओं को लंबे समय से दुनिया भर के दूर–दराज के देशों में निर्यात किया जाता थी। वैश्वीकरण की अवधारणा भारत के लिए शायद ही नई हो।विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व व्यापार का 2.7 प्रतिशत (2015 तक) खाता है, जो 2006 में 1.2 प्रतिशत था। 1991 के उदारीकरण तक, अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत बड़े पैमाने पर और जानबूझकर विश्व बाजारों से अलग–थलग था। विदेशी व्यापार आयात शुल्क, निर्यात कर और मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन था, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ऊपरी–सीमा इक्विटी भागीदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंध, निर्यात दायित्वों और सरकारी अनुमोदनों द्वारा प्रतिबंधित था; औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत नए थ्क् के लिए इन स्वीकृतियों की आवश्यकता थी।प्रतिबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि 1985 और 1991 के बीच एफडीआई का औसत सालाना लगभग +200M था; पूंजी प्रवाह के एक बड़े प्रतिशत में विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीयों की जमा राशि शामिल थी।

स्वतंत्रता के बाद पहले 15 वर्षों के लिए चाय, जूट और कपास के निर्माण की प्रबलता के कारण भारत का निर्यात स्थिर था, जिसकी मांग आम तौर पर बेलोचदार थी। नवजात औद्योगीकरण के कारण इसी अवधि में आयात में मुख्य रूप से मशीनरी, उपकरण और कच्चे माल शामिल थे। उदारीकरण के बाद से, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य अधिक व्यापक हो गया है और 1950–51 में 12.50 बिलियन से बढ़कर 2003–04 में 63,0801 बिलियन हो गया है। उद्धरण वांछित, भारत के व्यापारिक साझेदार चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात हैं। ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ।अप्रैल 2007 के दौरान निर्यात 16 प्रतिशत बढ़कर 12.31 बिलियन डॉलर और आयात 17.68 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.06 प्रतिशत अधिक था। भारत 1947 से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (जी.ए.टी.टी.) का संस्थापक सदस्य है और इसका उत्तराधिकारी विश्व व्यापार संगठन है। इसकी सामान्य परिषद की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, भारत विकासशील दुनिया की चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए, भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. नीतियों में श्रम और पर्यावरण के मुद्दों और अन्य गैर–टैरिफ बाधाओं जैसे मामलों को शामिल करने के लिए अपना विरोध जारी रखा है।2000 के दशक में कई बार आयात प्रतिबंधों को कम करने के बावजूद 2008 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत का मूल्यांकन ब्राजील, चीन और रूस जैसी समान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक के रूप में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन ने भी व्यापार पर महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में बिजली की कमी और अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढांचे की पहचान की।[1] इसकी प्रतिबंधात्मकता को एक कारक के रूप में उद्धृत किया गया है जिसने इसे 2008–2009 के वैश्विक वित्तीय संकट से अन्य देशों की तुलना में अलग कर दिया, भले ही इसने आर्थिक विकास में कमी का अनुभव किया।[2]

भुगतान–आजादी के बाद से, भारत के चालू खाते पर भुगतान संतुलन नकारात्मक रहा है। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद से (भुगतान संकट के संतुलन से उपजी), भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जो 2002–03 में इसके आयात का 80.3 प्रतिशत था, जो 1990–91 में 66.2 प्रतिशत था। हालांकि भारत अभी भी एक शुद्ध आयातक है, 1996–97 के बाद से, इसका समग्र भुगतान संतुलन (यानी, पूंजी खाता शेष सहित), सकारात्मक रहा है, मोटे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीयों से जमा राशि के कारण; इस समय तक, बाहरी सहायता और वाणिज्यिक उधार के कारण समग्र संतुलन कभी–कभार ही सकारात्मक था। परिणामस्वरूप, 2008 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 285 बिलियन डॉलर था, जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने पर देश के बुनियादी ढांचे के विकास में उपयोग किया जा सकता है। सितंबर 2017 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार+400 बिलियन को पार कर गया।[3] 1991–92 के बाद से बाहरी सहायता और वाणिज्यिक उधार पर भारत की निर्भरता कम हुई है, और 2002–03 से, वह धीरे–धीरे इन ऋणों को चुका रहा है। ब्याज दरों में गिरावट और कम उधारी ने 2007 में भारत के ऋण सेवा अनुपात को घटाकर 4.5

प्रतिशत कर दिया। भारत में, भारतीय कॉरपोरेट्स को धन का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बाहरी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) की अनुमति दी जा रही है। वित्त मंत्रालय ई.सी.बी. नीति दिशा–निर्देशों के माध्यम से इन उधारों (ई.सी.बी.) की निगरानी और नियमन करता है।

अर्थव्यवस्था–1991 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई है। भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसकी औसत वार्षिक दर 3.5 प्रतिशत (1990–1980) से बढ़कर 7.7 प्रतिशत (2002–2012) हो गई है। 2005 से 2008 तक यह दर 9.5 प्रतिशत पर पहुँच गई। आर्थिक विकास ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भी वृद्धि की है, जो 1978 में 1,255 डॉलर से बढ़कर 2005 में 3,452 डॉलर और अंत में 2022 में 8,358 डॉलर हो गया।[4]

प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में नौकरियों के कई लाभ हैं। हालांकि इसका फायदा उन सेक्टर के लोगों को ही हो रहा है। देश के लिए समग्र रोजगार दर में कमी आई है, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या 2.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है। इन आंकड़ों के बावजूद जी.डी.पी. हर साल बढ़ रही है। विकास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों तक सीमित है। बिहार, उत्तर प्रदेश (यू.पी.), ओडिशा, मध्य प्रदेश (एम.पी.), असम और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्य गरीबी से त्रस्त हैं।[5]

निवेश–1990 में 0-1% की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक पहुंच गया है, और अन्य देशों में भारतीय निवेश 2006 में तेजी से बढ़ा है।[6]

पी.पी.पी. के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत एफ.डी.आई. के लिए एक पसंदीदा स्थान है;[7]भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ऑटो घटक, रसायन, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स और आभूषण में ताकत है। विदेशी निवेश में वृद्धि के बावजूद, कठोर थ्क् नीतियों के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि, अर्थव्यवस्था को विनियमित करने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए गए कुछ सकारात्मक आर्थिक सुधारों के कारण, भारत ने खुद को तेजी से बढ़ते एशिया–प्रशांत क्षेत्र के अग्रणी धावकों में से एक के रूप में स्थापित किया है। भारत के पास कुशल प्रबंधकीय और तकनीकी विशेषज्ञता का एक बड़ा पूल है। मध्यम वर्ग की आबादी का आकार 50 मिलियन है और यह बढ़ते हुए उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।

2005 तक भारत की उदारीकृत एफ.डी.आई. नीति ने उद्यमों में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. हिस्सेदारी की अनुमति दी। औद्योगिक नीति सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया है, विस्तार पर प्रतिबंध हटा दिया है और विदेशी प्रौद्योगिकी और एफ.डी.आई. तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान की है। रीयल–एस्टेट क्षेत्र के ऊपर की ओर बढ़ते विकास वक्र का कुछ श्रेय उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उदारीकृत थ्क् व्यवस्था को जाता है। मार्च 2005 में, सरकार ने निर्माण व्यवसाय में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट–अप इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, कमर्शियल परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजक सुविधाओं और शहर और क्षेत्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित निर्माण विकास परियोजनाओं में इस स्वचालित मार्ग की अनुमति दी गई है।

अधिकांश क्षेत्रों में सीमा को हटाने के लिए एफ.डी.आई. नीति में कई बदलावों को मंजूरी दी गई। जिन क्षेत्रों में एफ.डी.आई. प्रतिबंधों में छूट की आवश्यकता है उनमें नागरिक उड्डयन, निर्माण विकास, औद्योगिक पार्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कमोडिटी एक्सचेंज, क्रेडिट–सूचना सेवाएं और खनन शामिल हैं। लेकिन यह अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बीमा और खुदरा बिक्री में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति देने का एक अधूरा एजेंडा छोड़ गया है। औद्योगिक सहायता के लिए सरकार के सचिवालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2006/07 (अप्रैल–मार्च) में भारत में एफ.डी.आई. प्रवाह 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। यह पिछले वित्त वर्ष में कुल US $7-8bn के दोगुने से भी अधिक था। 2007–08 के लिए FDI प्रवाह +24bn के रूप में रिपोर्ट किया गया है और 2008–09 के लिए, यह +35 बिलियन से ऊपर होने की उम्मीद है।भारत के निरंतर आर्थिक विकास को निर्धारित करने और आर्थिक महाशक्ति बनने की क्षमता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कारक इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रों में एफ.डी.आई. प्रवाह के लिए प्रोत्साहन कैसे बना सकती है।सितंबर 2012 में सरकार ने गठबंधन दलों के भारी दबाव के बावजूद बहु–ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. को मंजूरी दी। 2019 में, सरकार ने कोयला खनन में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी।

भारत को विप्रेषण–भारत में प्रेषण देश के बाहर कार्यरत भारतीय श्रमिकों द्वारा भारत में दोस्तों या रिश्तेदारों को धन हस्तांतरण है। 1991 के बाद से, भारत ने तीव्र प्रेषण वृद्धि का अनुभव किया है, और अब यह प्रेषण का दुनिया का अग्रणी प्राप्तकर्ता है। 1991 में, भारतीय प्रेषण कुल 2.1 बिलियन अमरीकी डालर था;2006 में, उनका अनुमान 22 बिलियन डॉलर और 25.7 बिलियन डॉलर

के बीच था, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत भारत ने 2007 में दुनिया के 12 प्रतिशत से अधिक प्रेषण का दावा किया। 2017 में प्रेषण लगभग 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने उन नौकरियों को बदल दिया है जिनके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और उच्च उत्तरदायित्व के साथ व्यापक रूप से परिभाषित नौकरियों के लिए निर्णय लेने के कौशल की कमी होती है जिसके लिए संख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, संचार और इंटरैक्टिव कौशल जैसे नए कौशल की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। प्रौद्योगिकी ने भी कई फर्मों को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल में अधिक स्वतंत्रता देने के लिए प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, गैर–नियमित कार्य करने वाले कर्मचारियों को न करने वाले श्रमिकों की तुलना में अधिक लाभ होता है।

9 अगस्त 1995 को नेटस्केप के सार्वजनिक होने से भारत को अत्यधिक मदद मिली। नेटस्केप ने तीन प्रमुख तरीकों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्वीकरण प्रदान किया। सबसे पहले, नेटस्केप ने ब्राउज़र के लिए वेबसाइटों से चित्र प्रदर्शित करना संभव बनाया। दूसरा, डॉट–कॉम बूम और डॉट कॉम बबल से प्रभावित फाइबर–ऑप्टिक दूरसंचार में अरबों के निवेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी मुद्रा डाली, उद्धरण वांछित। अंत में, प्रौद्योगिकी में अत्यधिक निवेश ने वैश्विक फाइबर नेटवर्क बनाकर इसे सस्ता बना दिया, जिससे डेटा संचारित करना आसान और तेज़ हो गया। नेटस्केप आई.पी.ओ. के परिणामस्वरूप, भारतीयों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए, जिनमें अन्य देशों से आउटसोर्स किए गए अवसर भी शामिल हैं। नौकरी के अवसरों में एक मील का पत्थर तब था जब Y2K बग को ठीक करने के लिए हजारों भारतीय इंजीनियरों को काम पर रखा गया था। यह काम और भी कई कंपनियों को दिया जा सकता था, लेकिन इसे भारत को आउटसोर्स कर दिया गया। भारत को अब एक अलग रोशनी में देखा जा रहा था, क्योंकि वह कार्यबल में शामिल होने के साथ–साथ नौकरियों के लिए पहली दुनिया के देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था।

कृषि–यद्यपि भारत में अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ है, देश के सभी क्षेत्रों को लाभ नहीं हुआ है। जो धन कृषि क्षेत्र को निर्देशित किया जाना चाहिए था वह निजी क्षेत्र के उद्यमों को निर्देशित किया गया था। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र में विकास 2007 में 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 2.6 प्रतिशत हो गया। विकास में इस गिरावट ने किसानों को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि उत्पादन लागत बहुत अधिक है, जबकि कमोडिटी लागत कम है। इसके परिणामस्वरूप 1997 से अब तक 150,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

एक अन्य तरीके से वैश्वीकरण ने कृषि क्षेत्र को जैव ईंधन और औषधीय खेती के माध्यम से प्रभावित किया है। भारत में खाद्य सुरक्षा संकट है क्योंकि जैव ईंधन के लिए फसल उगाने के लिए भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्दिष्ट किया गया है। चावल और गेहूँ जैसी फसलें अक्सर बड़ी मात्रा में काटी जाती हैं। हालाँकि, जैव ईंधन के लिए उपयोग की जाने वाली फसलों की मात्रा काफी हद तक अनियमित है, जिसमें अपर्याप्त राशि गरीबों और ज़रूरतमंदों के पास जाती है।

प्रौद्योगिकी ने भारत में शिक्षा की पहुँच में भी वृद्धि की है, विशेषकर महिलाओं के लिए। इसने पुरुषों और महिलाओं के बीच की खाई को कम किया है जो स्तरीकृत लिंग भूमिकाओं द्वारा बनाई गई थी। इसने महिलाओं को भी दो तरह से सशक्त बनाया है। प्रौद्योगिकी ने अधिक महिलाओं को सामाजिक विज्ञान और मानविकी में उनकी पारंपरिक डिग्री के बजाय कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में उन्नत डिग्री हासिल करने के लिए प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता का विस्तार किया। बदले में, इसका भारत में अकेली महिला के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। अकेली महिलाओं के कलंक और अपेक्षाओं में कमी आई है। उदाहरण के लिए, अकेली महिलाओं के लिए कोलकाता जैसे शहरों में रहने की जगह ढूँढ़ना आसान है। समाज तब महिलाओं पर एक निश्चित उम्र में शादी करने के लिए कम दबाव डालता है क्योंकि उच्च शिक्षा अब अधिक स्वीकार्य है। भारत युवाओं के लिए भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। नए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, और हाई स्कूल स्नातकों की बढ़ती आबादी को आकर्षित करने के लिए होर्डिंग पर विज्ञापन कोलकाता के चारों ओर बढ़ गए हैं।

शिक्षा–भारत ने विश्वविद्यालयों के प्रसार के माध्यम से भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जबकि 2014 तक 6.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे, यह अभी भी 2006 में 13.46 मिलियन से एक महत्वपूर्ण सुधार था। भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश किया है, लेकिन निजी हितों की मदद से और अधिक प्रगति की जा सकती है। साक्षरता दर और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त वित्तीय शक्ति है। यह निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही, वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित किया जा सकता है ताकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य को पाठ्यक्रम में तय किया जा सके। वैश्विक शिक्षा के चार पहलू जिन पर भारत के विश्वविद्यालय ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वे हैं

वैश्विक पाठ्यक्रम, वैश्विक संकाय, वैश्विक डिग्री और वैश्विक संपर्क। ये पहलू न केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, बल्कि वैश्वीकरण द्वारा पैदा की जा रही बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को तैयार करने में भी मदद करेंगे।

स्वास्थ्य–एक अन्य क्षेत्र जिसे सरकार ने उपेक्षित किया है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य है। भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य व्यय का अनुपात सबसे कम है। सबसे अमीर 20 प्रतिशत आबादी के लिए शिशु मृत्यु दर केवल 38 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जबकि सबसे गरीब 20 प्रतिशत की दर 97 प्रति 1000 है। साथ ही, गरीबों के बीच महामारी की दर बढ़ रही है; ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस/एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एचआईवी/एड्स) और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों का प्रकोप होना आम बात है।

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत : जून 2002। विश्व व्यापार संगठन व्यापार नीति की समीक्षा।
2. भारतीय रिजर्व बैंक–साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक"।
3. मजूमदार, सुमित के. "वैश्वीकरण और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सापेक्ष मुआवजा।" सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय विकास 6.1 (2010): 21–33। व्यापार स्रोत प्रीमियर। वेब। 16 जनवरी 2015।
4. शर्मा, शैलेंद्र डी. "'इंडिया राइजिंग' एंड द मिक्स्ड ब्लेसिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन।" भारत त्रैमासिक 70.4 (2014): 283–297। अकादमिक खोज प्रीमियर। वेब। 16 जनवरी 2015।
5. भारत का अधिकांश एफ.डी.आई. मॉरीशस के माध्यम से होता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचने का समझौता है। "भारत मॉरीशस के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा"। 15 अगस्त 2005 को पुनःप्राप्त।
6. एफ.डी.आई. इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स" (पीडीएफ)। मूल (पीडीएफ) से 2 दिसंबर 2016 को पुरालेखित। 13 जनवरी 2017 को लिया गया।
7. ए.बी. "बिज निवेश के लिए भारत दूसरा सबसे अच्छा देशः सर्वेक्षण– द फाइनेंशियल एक्सप्रेस"। Financiale-press-com. अगस्त 2008. 3 नवंबर 2008 को पुनःप्राप्त।
8. नेक्स्ट बिग स्पेंडर्सः इंडियाज़ मिडिल क्लास